

Title of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - Srinagar (Km.-195.200,000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नकुवाड

तहसील चौबेरावा, जिला पौड़ी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जंगल पौड़ी के अन्तर्गत 195.200 से 276.000 तक NH-119 परियोजना के निर्माण हेतु (4.367) हे० 42 सठ्क आवंटित वन भूमि, 20.115 हे० शिविल सोयम भूमि 4.151 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 24.266 हे० वन भूमि का चौबेरावा वि. श्रीनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नकुवाड द्वारा दिनांक 7/4/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेंडरी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किराी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किराी गैर आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

घरों के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौबेरावा, नकुवाड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेंडरी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० AD
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत अधिकारी
जमशेदपुर जिला नकुवाड
विभाग/संस्था चौबेरावा वि. श्रीनगर
मुख्य कार्यालय उत्तराखण्ड

अनिता नेनी
अतिरिक्त प्रमुख एक्सेक्यूटिव
ग्राम-नकुवाड पो-पाटीरीन
पौड़ी नकुवाड (उत्तराखण्ड)



ग्राम प्रधान/संरक्षक
सुहर सहित

प्रा.प - 30.3

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=200
मनपुरी - कालपा - श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डांग

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत की

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे0) आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि
हे0, वन पंचायत भूमि 0.15 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 का भूमि का राजस्व वन
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डांग द्वारा दिनांक 31/12/2016 को

सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों
के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा
नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के
निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परमपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम डांग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के कि0मी0 195=200 से 276=200
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

8
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डांग
वि0सं0 पौड़ी गढ़वाल



प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-200 से 276.000 सतपुली-जलपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम विष्णु गंगा

तहसील पूँछी जिला पूँछी (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पूँछी-गढ़वाल के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि, 7-42 मसला निलम्बरु

हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याशित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विष्णु गंगा द्वारा दिनांक 31/12/2016

सम्बन्धित ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा साफ्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौली, इरीलीजगा नौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि श्रीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
वि0ख0. पूँछी (गढ़वाल)

ह0/-
ग्राम प्रधान/संस्था
मुख्य अधिकारी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=200
सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम..... नौगांव

तहसील..... पौड़ी जिला..... पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 195=200 से 276=200 सतपुली
ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क NH-

19 की चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (4.36 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि.....
1.12 सड़क चौड़ाई निम्नलिखित..... हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 32.533 हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नौगांव द्वारा दिनांक 02/01/2019 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संरक्ष में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नौगांव ज्वालपा सेवा, कोण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 276 सीन 119 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत अधिकारी अधिकारी
ग्राम पंचायत सदस्य नौगांव
दिनांक 02.01.2019 पौड़ी गढ़वाल



प्रा०- 30.3

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि०मी० 195.200 से 276.200
सतपुली-जालपा-शीतगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चि०डा०

तहसील चि०डा० जिला चि०डा० गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चि०डा० गढ़वाल के अन्तर्गत एम-119 सतपुली से शीतगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे० आरक्षित वन भूमि, 30.115 हे० सिविल सोयम भूमि

742 सतपुली विस्तार हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 32.553 हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चि०डा० द्वारा दिनांक 30/12/2016 को

सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चि०डा०, नौडियालगाव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 सतपुली से शीतगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ह०/-
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चि०डा०
चि०डा० गढ़वाल

ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुली-खीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम डूंग-रेवाणा
तहसील सिहार जिला पश्चिम बंगाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद डूंग-रेवाणा के अन्तर्गत MM-119 (S34) सतपुली से खीनगर
परियोजना के निर्माण हेतु (4.867) हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि,
7092 मसुवा निवासी हे0, वन पंचायत भूमि 0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का 21.031 वन
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डूंग-रेवाणा द्वारा दिनांक 02/03/2017 को
सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों
के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा
नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी
अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के
निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि
ग्राम डूंग-रेवाणा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुलाकोट
प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित पंचायत
विकास खण्ड डूंग-रेवाणा
जनपद डूंग-रेवाणा



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195-200 से 276-00 सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अणेश

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत मन्ना 19 सतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.1367 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि

7.42 मक्का निकार 3 हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 32.553 हे० वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अणेश द्वारा दिनांक 01/01/2017 को

सम्बन्धित ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर
ग्राम संचायक विकास अधिकारी
ग्राम संचायक अ. 0. 19
वि० ख०. के. १११ गढ़वाल



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०९४० १११ के कि०मी० १९५-२०० से २७६.०००
सतपुली-कोलपा-शीनगर को लेन सड़क चौड़ी करण बाबत:

वन अधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पीपली

तहसील पेड़िया जिला पेड़िया गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पेड़िया गढ़वाल के अन्तर्गत १५-११९ सतपुली से शीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (४:३६.५ हे० आरक्षित वन भूमि, २०:११.५ हे० सिविल संगम भूमि, ५२ मज्जा मिटर हे०) वन पंचायत भूमि (१५१ हे०) अर्थात् कुल ३२.५८३ हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पीपली द्वारा दिनांक ३०/१२/२०१६ को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। सर्वेक्षित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि पीपली-सतपुली-शीनगर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राजस्व वन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर :-
 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत पीपली
 वि० सं० पेड़िया गढ़वाल

हस्ताक्षर :-
 ग्राम प्रधान/समस्त
 गृह सचिव

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 19.522^{km} से 27.62^{km} अनूपली-जगहना-झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण दावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम अगरीडा

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद

पौड़ी गढ़वाल

19.522^{km} से 27.62^{km} तक NH
119 सड़क चौड़ीकरण की

परियोजना के निर्माण हेतु (4.26^{ha} हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि, 74.2 मालती निस्कार हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 28.553 हे० वन भूमि का राजख वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अगरीडा द्वारा दिनांक 31/12/2016 को

सम्पन्न ग्राम/राभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आपलू लुगा रांग, मराडा, गौली रांग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 119 से 27.62^{km} तक झीनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिरो जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत अधिकारी
वि०ख०. गढ़वाल

प्राकृतिक देवी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर शाहिदा
पौड़ी

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 274+00 (सतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बाधत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रडली

तहसील घोडी जिला घोडी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत NH-119 सतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.267 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि

7.92 सप्ताह निस्वार्थ) हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 39.553 हे० वन भूमि का राजस्व वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रडली द्वारा दिनांक 19.03.12 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रडली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुन्नाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० Sudeep
ग्राम सचिव घोडी
मुहर सहित

ह० /
ग्राम प्रधान / सरपंच
मुहर सहित
कमल देवी
मुखिया

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सेतुपुली-भीनमर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम श्री कोट खण्ड

तहसील भीनमर जिला श्री गंगानगर

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद श्री गंगानगर के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु (4.364 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि

7-92 अथवा जितना है) हे0, वन पंचायत भूमि (0.151 हे0) अर्थात कुल 24.553 हे0 वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत श्री कोट खण्ड द्वारा दिनांक 2/8/13 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम श्री कोट खण्ड के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, धुमाकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित


ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत श्री कोट खण्ड
तहसील भीनमर
जिला श्री गंगानगर



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00 सतपुली-जालपा-झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम थापली (कफोलखुं)

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल

195=200 से 276=00 सतपुली-जालपा-झीनगर तक नम-119

सड़क पौड़ी गढ़वाल परियोजना के निर्माण हेतु (4:26:7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20:11:5 हे0 सिविल सोरम भूमि, 7-92 मम्बा निलम्ब हे0, वन पंचायत भूमि 0:15:1 हे0) अर्थात् कुल 32:55:3 हे0 वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थापली (कफोलखुं) द्वारा दिनांक 31/12/2016 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थापली, पौड़ी, जरेवेरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नम-119 परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत थापली
दिनांक 01/01/2017 गढ़वाल



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=07
सतपुरी - ज्वालपा - झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम हकीली विष्ट

तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ज्वालपा - झीनगर तक NH
119 सतपुरी परियोजना के निर्माण हेतु (4.36.7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि, 7.92 मगला निरंतर) हे0, वन पंचायत भूमि (0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राज्य वन
विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के दिषय में ग्राम पंचायत हकीली विष्ट द्वारा दिनांक 01/01/2017 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतपुरी पल्ता के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=07 सतपुरी - ज्वालपा - झीनगर परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत
मुहर सहित
वि०ख० पौड़ी गढ़वाल



ह०/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्र० प्र०, हकीली विष्ट
पौड़ी गढ़वाल

समय - वि. रेवडी

परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० 119 के कि०मी० 196+00 से 276+00 (संतपुली-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बायत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम वि. रेवडी

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत म.प. 119 संतपुली से श्रीनगर

परियोजना के निर्माण हेतु (4.367 हे० आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि, 7.92 म.प. वि. रेवडी हे०, वन पंचायत भूमि 0.151 हे०) अर्थात् कुल 32.533 हे० वन भूमि का राज्य वन

विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रेवडी तनी द्वारा दिनांक 14/11/20 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिधति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेवडी तनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/स० चौहान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

ह०/स० म.प. वि. रेवडी
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुखर सहित म.प. वि. रेवडी
पौड़ी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 195=200 से 276=00
सातपुली - जालण - झीनगर दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तोली

तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 195=200 से 276=00 सातपुली - जालण - झीनगर तक NH 119

सड़क चौड़ीकरण परियोजना के निर्माण हेतु (4.36 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.115 हे0 सिविल सोयम भूमि, 7.99 हे0 मजदूरी के लिए) वन पंचायत भूमि (0.151 हे0) अर्थात् कुल 32.553 हे0 वन भूमि का राजस्व वन विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तोली द्वारा दिनांक 02/01/2017 को सम्पन्न ग्राम/सभा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि तोली, दाहिगाँव बल्ला, दाहिगाँव पल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के निर्माण प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

20/01/2017
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम पंचायत तोली
तहसील पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 196+00 से 276+00 (सतपुरी-भीनमर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बावत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....

तहसील..... जिला.....

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद..... के अन्तर्गत.....

परियोजना के निर्माण हेतु (4.26.7 हे0 आरक्षित वन भूमि, 20.11.5 हे0 सिविल सोयम भूमि.....
742 म.म.मी. निम्नलिखित..... हे0, वन पंचायत भूमि 0.15.1 हे0) अर्थात् कुल 32.33 हे0 वन भूमि का राजस्व 99-
..... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत..... द्वारा दिनांक 18/11/16 को सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग धुमकेट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्रधान ग्राम पंचायत
दिनांक 18/11/16
तहसील-चौबुटाल

परियोजना का नाम :- सड़क राजमार्ग संख्या एनएच 118 के किन्चि 196+00 से 276+00 (सतपुरी-श्रीनगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण बायत।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कमेटा पंचायत

तहसील सतपुरी जिला सतपुरी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत NH-118 (535) रूखुती दे कीम

परियोजना के निर्माण हेतु (4.26.1 हे० आश्रित वन भूमि 20.1.15 हे० सिविल सोयभूमि 7.92 म० की 1-11/12 हे० वन पंचायत भूमि 1.51 हे०) अर्थात् कुल 30.88 हे० वन भूमि का सतपुरी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कमेटा द्वारा दिनांक 24/01/17 को सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के लब्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 को प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परमेश्वर अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कमेटा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सतपुरी रूखुती दे कीम प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित



परियोजना का नाम - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन०एच० ११९ के कि०मी० १९६+०० से २७६+०० (सतपुड़ी-भीमगर) दो लेन सड़क चौड़ी करण कार्य।

वन अधिनियम अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सतपुड़ी

तहसील सतपुड़ी जिला सतपुड़ी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद सतपुड़ी के अन्तर्गत NH-119 (सतपुड़ी से भीमगर)

परियोजना के निर्माण हेतु (41.3651 हे० आरक्षित वन भूमि 20.115 हे० सिविल सोयम भूमि 7.92 हे०) वन पंचायत भूमि 1.51 हे०) अर्थात् कुल 32.0553 हे० वन भूमि का सतपुड़ी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सतपुड़ी द्वारा दिनांक 14/01/19 को सम्पन्न ग्राम/समा पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

घरों के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सतपुड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि सतपुड़ी परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा शक्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर

ग्राम पंचायत

सिखार

ह०/-

ग्राम प्रधान/संरक्ष

मुहर सहित

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के कि0मी0 194+00 से 224+00 (उत्तराखण्ड) में लेन सड़क चौड़ी करण बाबत।

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम सुन्दरपुरा

तहसील पिंडी जिला पिंडी (उत्तराखण्ड)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में राजपथ

पिंडी

के अन्तर्गत NH-119 सड़की से होकर

परियोजना के निर्माण हेतु (4:36:11) हे0 आकृति का भूमि 20:115 हे0 सिविल सीमम भूमि 7-92 मजदारी मिलान हे0 वन पंचायत भूमि 0.151 हे0 अर्थात् कुल 20.53 हे0 वन भूमि का राजपथ वन विभाग/संस्था के फस में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्षित करने हेतु अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रस्ताव के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत पुनराप द्वारा दिनांक 08/01/17 को सम्पन्न ग्राम/समा में वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसकी अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वर्षा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वेक्षण से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सुन्दरपुरा के डोबला गाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग शुभाफोर प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

सुन्दरपुरा
ग्राम पंचायत
वि०ख० पिंडी

ग्राम पंचायत
वि०ख० पिंडी

ग्राम प्रधान/सचिव सुन्दरपुरा
मुहर सहित

Name of Project :- Diversion of Forest Land for Widening and up gradation to 2 lane with configuration from Satpuli - Jwalpa - S rinagar (Km.-195.200.000 to 276.000) section NH-119 in Pauri Forest Division of Pauri District.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रोहरी / डोवला
तहसील रोहरी, जिला पौड़ी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी के अन्तर्गत NH-119 के कि० मी० 195 से 276 तक 1.317 हे० सिविल सोयम भूमि परियोजना के निर्माण हेतु (1.317 हे० आरक्षित वन भूमि हे० सिविल सोयम भूमि हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.317 हे० वन भूमि का 1.317 हे० विभाग/संस्था के प्ल में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रोहरी / डोवला द्वारा दिनांक 07/09/16 को सामान्यतः ग्राम/ग्राम पंचायत के बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आर्क्षित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

इसके उपरान्त ग्राम/ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पेश किया गया कि ग्राम रोहरी / डोवला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित



ग्राम सचिव डोवला



परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119 के वि०पी० 108+00 से 108+00 (रहोतह-सदामुली) दो लेन सड़क चौड़ी करण आका।

वन अधिकार विधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पेड़वा

तहसील पेड़वा जिला पेड़वा (2169/1)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड पेड़वा

के अन्तर्गत

परियोजना के निर्माण हेतु (4.36.2.1.80 अर्थात् वन भूमि, 10.115.80 विविध वन भूमि, 7.4.2. मूलभूत निर्माण हेतु वन पंचायत भूमि 0.151.80) अर्थात् कुल 22.553.80 वन भूमि का 22.553.80 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पेड़वा द्वारा दिनांक 08/01/17 को सम्मान 103/104 पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सक्ता में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

कर्ता के उपरान्त ग्राम स्तर द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पेड़वा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु देने जहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/-
ग्राम सचिव पेड़वा
मुख्य सचिव पेड़वा

